

मुकदमों का विवरण

ए. वल्लियामाई बनाम

के. पी. मुराली और अन्य (2023 की सिविल अपील संख्या 5342) 12 सितंबर, 2023

[संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या विशिष्ट ग निष्पादन के लिए वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था और क्या उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित विशिष्ट ग निष्पादन के निर्णय और डिक्री को लागू करने में गलती की थी।

विनिर्दिष्ट ग निष्पादन-अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं-विनिर्दिष्ट ग निष्पादन के लिए सूट-सीमा-सीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 54-प्रयोज्यता:

आयोजित किया गया: सीमा अधिनियम की अनुसूची के भाग II के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट ग निष्पादन के लिए मुकदमे के लिए सीमा अवधि निर्धारित की गई है जो निष्पादन के लिए निर्धारित तिथि से तीन साल है, और वैकल्पिक रूप से जब कोई तारीख निर्धारित नहीं की जाती है, उस तारीख से तीन साल जब वादी को पता चलता है कि निष्पादन से इनकार कर दिया गया है-वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि बेचने के समझौते के निष्पादन के समय अग्रिम का भुगतान किया गया था।⁸⁸, और शेष राशि का भुगतान 26.05.89 द्वारा किया जाना आवश्यक था-हालाँकि, इसके भुगतान और बिक्री विलेख के निष्पादन का समय 26.11.89 तक बढ़ा दिया गया था। 26.05.89 – यदि, 26.11.89 को निष्पादन की तारीख के रूप में लिया जाता है, तो 27.09.95 पर निर्दिष्ट विशिष्ट कार्य निष्पादन के लिए मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है-हालाँकि, उपरोक्त समय, जैसा कि बेचने के समझौते और समर्थन के अनुसार, अनुबंध का सार नहीं था और इसलिए, अनुच्छेद 54 का पहला भाग लागू नहीं होगा-इसके बजाय, अनुच्छेद 54 का दूसरा भाग लागू होगा-विशिष्ट कार्य निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए 3 साल की सीमा अवधि उतनी जल्दी शुरू हो जाएगी जब प्रतिवादी नं. 3 15.07.91-अपीलार्थी (C.A.No में) पर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था। 2023 का 5342) का उत्तर डी. टी. डी. 09.08.1991 या प्रत्युत्तर डी. टी. डी. को जवाब दें। 16.09.1991 उत्तरदाता को फिर से पर्याप्त लिखित सूचना दी गई थी।³ उसका

183 184

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

बेचने के लिए समझौते को पूरा करने से इनकार और अनिच्छा-अनुच्छेद 54 के दूसरे भाग के तहत तीन साल की सीमा अवधि, जो उस तारीख से है जब पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा इनकार करने की सूचना मिली थी, तब समाप्त हो गई थी जब विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए मुकदमा 27.09.1995 पर किया गया था-इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या के नेतृत्व में विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए मुकदमा। 3 'एस असाइनीज ('केपीएम' और 'एसपीडी') को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है-डिवीजन बेंच द्वारा निर्दिष्ट सी प्रदर्शन के लिए विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है-हालाँकि, तथ्यों पर, पर्याप्त न्याय करने के लिए, अपीलार्थी के खिलाफ 'केपीएम' और 'एसपीडी' के पक्ष में, 6 महीने के भीतर इसका भुगतान करने में विफल रहने पर, 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी के खिलाफ, 'आईडी1', 00,000/- का डिक्री पारित किया जाता है-सिविल अपील संख्या 5343, 5344 और 2023 की 5345 एफआई, वाद संपत्ति के भागों के बाद के खरीदारों के नेतृत्व में, अनुमति दी जाती है-अपीलार्थी के नेतृत्व में 2023 की सिविल अपील संख्या 5342 की सीमा तक अनुमति दी जाती है। एस. 63. [पैरा 20, 21 और 27-29]

पचानन धारा और अन्य बनाम मोनमाता नाथ मैती (2006) 5 एस. सी. सी.

340 :[2006] 2 पूरक।एस. सी. आर. 520-पर निर्भर।

एस. ब्रह्मानंद और ओआरएस. वी.के. आर. मुत्तुगोपाल, (2005) 12 एस. सी. सी. 764:[2005]

4 पूरक।एस. सी. आर. 461-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 5342।2007 के ए. एस. No.63 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2016 से।

के साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 5343, 5344 और 5345।

रूप:

रंजीत कुमार, जयदीप गुप्ता, पल्लव सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता।, जी. बालाजी, सुश्री शासे, के. एस. महादेवन, श्रीमती स्वाति बंसल, रंगराजन आर., राजेश कुमार, आर. अय्यम पेरुमल, आनंद साथियासीलन, राकेश शर्मा, अक्षय गोयल, अनुराग सहाय, रजत सहगल, सम्यक जैन, एस. महेंद्रन, सत्येंद्र कुमार, एस. गौतम, बी. करुणाकरन, श्रीमती.

185

ए. वल्लियामई बनाम के. पी. मुराली और अन्य 186

के. बालम्बीहाई, अजीत विलियम एस, पी. शंकर, अजय परबू एस., अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजीव खन्ना (न्यायाधीश)

2017 की आई. ए. संख्या 1 और 2023 की 27407।

1. दस्तावेजों की प्रकृति में अतिरिक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति के लिए 2017 की आई. ए. संख्या 1 और 2023 की 27407 का विरोध नहीं किया जाता है।तदनुसार, 2017 की आई. ए. संख्या 1 और 2023 की 27407 को अनुमति दी गई है।दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया जाता है।वर्ष 2017 के आई. ए. सं. 1 में सं. 2-12 को प्रदर्शनी सं. एस.-1-एस.-11 के रूप में चिह्नित किया गया है और 2023 के आई. ए. सं. 27407 में सं. 2-4 को प्रदर्शनी सं. एस.-12-एस.-14 2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

2023 का सी. ए. संख्या 5342-5345।

1. मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2007 के अपील वाद (एम. डी.) संख्या 63 में दिनांक आई. डी. 1 का विवादित निर्णय, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा पारित विशिष्ट निष्पादन के निर्णय और डिक्री की पुष्टि करता है।

1 एस-1 प्रदर्शित करें-1991 के ओ. एस. सं. 508 में जिला मुन्सिफ अदालत द्वारा पारित दिनांकित 23.12.1992 निर्णय की एक सच्ची प्रति; एस-2 प्रदर्शित करें-दिनांकित वकील के नोटिस की एक वास्तविक प्रति 11.07.1994; एस-3 प्रदर्शित करें-

दिनांकित 13.07.1994 प्रत्युत्तर सूचना की एक वास्तविक प्रति; एस-4 प्रदर्शित करें-1994 के ओएस नंबर 1164 में जिला मुन्सिफ अदालत द्वारा पारित 12.06.2002 के फैसले की एक सही प्रति; एस-5 प्रदर्शित करें-पीडब्लू-1 के बयान की एक वास्तविक प्रति-वादी-दुरैसामी, 2004 की ओ. एस. संख्या 21 दिनांक 05.07.2004 में; एस-6 प्रदर्शित करें-डी. डब्ल्यू.-1 की गवाही की एक वास्तविक प्रति-प्रथम प्रतिवादी-के. श्रीराम 2004 के ओ. एस. संख्या 21 में दिनांक 07.09.2006; एस-7 को प्रदर्शित करें-डी. डब्ल्यू.-2-दूसरे प्रतिवादी-वल्लियम्मई के बयान की एक वास्तविक प्रति, 2004 के ओ. एस. नंबर 21 में दिनांक 15.09.2006; एस-8 प्रदर्शित करें-डी. डब्ल्यू.-3 के बयान की एक वास्तविक प्रति-2004 के ओ. एस. संख्या 21 में शिवकामी दिनांक 26.10.2006; एस-9 प्रदर्शित करें-डी. डब्ल्यू.-4 के बयान की एक वास्तविक प्रति-2004 के ओ. एस. संख्या 21 दिनांक 10.11.2006 में सिंगाराम; एस-10 प्रदर्शित करें-दिनांकित 08.05.1995 के बिक्री विलेख की एक वास्तविक प्रति, दिनांकित 28.11.1994 के पावर ऑफ अटॉर्नी विलेख के साथ; एस-11 प्रदर्शित करें-31.08.1991 दिनांकित सूचना की एक वास्तविक प्रति।

2 एस-12 प्रदर्शित करें-85 के ओएस नंबर 787 में पारित 03.11.1989 दिनांकित निर्णय/आदेश की एक सही प्रति और मूल की फोटोकॉपी के साथ 85 के ओएस नंबर 787 में डॉकेट आदेश; एस-13 प्रदर्शित करें-के. श्रीराम की ओर से दिनांक 31.08.1991 पर भेजे गए प्रत्युत्तर सूचना की एक सही प्रति; एस-14 प्रदर्शित करें-ए. वल्लियम्मई की ओर से दिनांक 16.09.1991 पर भेजे गए प्रत्युत्तर की एक सही प्रति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1, तिरुचिरापल्ली, दिनांक 28.12.2006, 2004 के O. S. नंबर 21 में।

2. 2023 की सिविल अपील संख्या 5342 में अपीलकर्ता ए. वल्लियम्मई है, जो कि सर्वेक्षण संख्या 55/2 बी1 और 55/2 बी2 के पश्चिम छोर पर 58, अगरम गांव, तिरुवेरंबूर उप-जिला, त्रिची जिले 3 में स्थित 11 एकड़ भूमि का कथित मालिक है, जिसे स्वर्गीय अयम्पेरुमल की दूसरी पत्नी होने के नाते विरासत में मिला है। सिविल अपील संख्या 2023 की 5343, 2023 की 5344 और 2023 की 5345 को एस. जयप्रकाश और अन्य, ए. जयकुमार और अन्य, और एस. बालासुब्रमण्यम और अन्य, जो बाद के खरीदार हैं जिन्होंने सूट संपत्ति के कुछ हिस्से खरीदे हैं, द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

3. ए. वल्लियम्मई ने प्रतिवादी संख्या के साथ दिनांकित 26.05.1988, प्रदर्शनी ए-1 को बेचने के लिए एक समझौता किया था। 3-के. श्रीराम, रुपये की दर से सूट संपत्ति की बिक्री के लिए। 2,95,000-प्रति एकड़। रु. की राशि। 1,00,000-के. श्रीराम द्वारा ए. वल्लियम्मई को अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था। रुपये की शेष बिक्री पर विचार। 31,45,000-का भुगतान 26.05.1988 से, यानी 26.05.1989 द्वारा, एक वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक था। हालांकि, दिनांक 26.05.1989, प्रदर्शनी A-3 के समर्थन के माध्यम से, शेष बिक्री विचार के भुगतान और बिक्री विलेख के निष्पादन की समय सीमा 6 महीने यानी 26.11.1989 तक बढ़ा दी गई थी।

4. इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए, इससे पहले कि हम विशिष्ट कार्य निष्पादन के लिए मुकदमे की अंतिम भाषा की ओर ले जाने वाले तथ्यों का उल्लेख करें, हम बेचने के समझौते के दो खंडों को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे (ए-1 प्रदर्शित करें)। खंडों में लिखा है:

“सर्वेक्षण संख्या 55/2 बी. 1 में, जो मेरे नाम पर बिक्री संपत्ति में पूर्व से पश्चिम में स्थित है, आयरमलाई ट्रस्ट के पक्ष में पूर्व छोर पर, उत्तर से दक्षिण में स्थित है और इसे स्थानांतरित करने के बाद सर्वेक्षण संख्या 55/2 बी. 1 और 2 बी. 2 से गुजरता है और फिर आपको संपत्तियां बेचता है, इसलिए जो 11 एकड़ संपत्तियां मैं आपको बेचता हूँ, वे पश्चिम छोर पर उपरोक्त दो सर्वेक्षण संख्याओं में स्थानांतरित हो जाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि जो एकमात्र संपत्तियां मैं आपको बेचता हूँ, वे सीमा के भीतर आएंगी।

3 संक्षेप में, "सूट प्रॉपर्टी"।

187

ए. वल्लियम्मई बनाम के. पी. मुराली और अन्य [संजीव खन्ना, जे.] 188

मैं आश्चर्य करता हूँ कि उप-न्यायालय में मूल मुकदमा संख्या 737/85 को छोड़कर वर्णित संपत्ति पर बोज़ या विवाद है। यदि बाद में कोई अड़चन या विवाद पाया जाता है, तो मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं उन अड़चनों और विवादों को अपनी जिम्मेदारी से सुलझाऊंगा।"

5. 11.07.1991 पर, के. श्रीराम ने अपने वकील, प्रदर्शनी ए-6 के माध्यम से एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें ए. वल्लियम्मई को शेष बिक्री पर विचार स्वीकार करने और एक महीने के भीतर बिक्री विलेख को निष्पादित करने की आवश्यकता थी। ए. वल्लियम्मई ने समझौते की तारीख से एक साल के भीतर के. श्रीराम या तीसरे व्यक्ति के पक्ष में एकल या कई विलेखों को निष्पादित करके बिक्री विलेख को निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की थी, जैसा कि उनके द्वारा सुझाव दिया गया था। 14.04.1991 पर ए. वल्लियम्मई ने रुपये की मांग की थी। 3,00,000-बिक्री विचार के एक हिस्से के रूप में, लेकिन 07.07.1991 पर, उसने रुपये स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 3,00,000-के. श्रीराम द्वारा जारी किया गया। इसके अलावा, ए. वल्लियम्मई ने सूट संपत्ति का केवल आधा हिस्सा बेचने की इच्छा व्यक्त की थी और वह भी रुपये के बढ़े हुए विचार पर। 4,17,000-प्रति एकड़। ए. वल्लियम्मई ने अय्यरमलाई ट्रस्ट 4 से संबंधित 4.4 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने का आश्वासन दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेचने के समझौते (प्रदर्शनी ए-1) के संदर्भ में बिक्री के तहत संपत्ति त्रिची से तंजावुर सड़क के बगल में स्थित है। अपने खर्च पर, के. श्रीराम ने इस तरह के धर्मांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने लेआउट योजना तैयार की थी, इसे त्रिवेम्बुर पंचायत संघ और मद्रास नगर योजना को उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था और आम भूमि को तिरुवेम्बुर पंचायत संघ को सौंप दिया था। ए. वल्लियम्मई ने ए. वल्लियम्मई के पति स्वर्गीय अय्यम्पेरुमल कोनार की पहली पत्नी राजामणि अम्मल के नेतृत्व में तिरुचि उप-न्यायालय में लंबित 1985 के ओएस नंबर 787 में विभाजन के मुकदमे को निपटाने का भी वादा किया था, जो सूट संपत्ति का मूल मालिक है।⁵

6. ए. वल्लियम्मई ने अपने वकील द्वारा दिनांकित 09.08.1991, प्रदर्शनी ए-7 द्वारा भेजे गए जवाब के माध्यम से जवाब दिया। उसने रुपये की मांग करने से इनकार कर दिया। 3,00,000-। इसके विपरीत, उन्होंने आरोप लगाया कि के. श्रीराम अनुबंध को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर बेचने (ए-1 को प्रदर्शित करने) के समझौते का पालन करने में विफल रहे। के. श्रीराम द्वारा लगाए गए आरोपों का आविष्कार बिक्री विलेख के निष्पादन को स्थगित करने के लिए किया गया था। उन्होंने मुश्किलों के कारण लेआउट योजना को रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

4 संक्षेप में, "विश्वास"।

5 राजामणि अम्मल और स्वर्गीय अय्यम्पेरुमल कोनार निःसंतान थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि के. श्रीराम ने लेआउट बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं किया था। यदि न्यास की संपत्ति पूर्व में आवंटित की जाती है, तभी वर्णित संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ओ. एस. नं. में विभाजन का मुकदमा 787 1985 का निपटान उसकी कीमत पर किया जाना था। के. श्रीराम को विचाराधीनता के बारे में पता था। विभाजन मुकदमे के निपटारे के बाद बिक्री विलेख का निष्पादन किया जाना था। ए. वल्लियम्मई संपत्ति को पहुँचाने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उक्त विभाजन मुकदमे का निपटारा नहीं किया गया था।

7. के. श्रीराम ने जवाब देते हुए कहा कि ए. वल्लियम्मई द्वारा लगाए गए आरोप गलत थे। ए. वल्लियम्मई खुद को समझौते से बाहर निकालना चाहते थे। वह बेचने के समझौते (प्रदर्शनी ए-1) के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था। बिक्री विलेख को निष्पादित करने की मांग पूर्व-परिपक्व नहीं थी। के. श्रीराम ने लेआउट योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। के. श्रीराम ने अपने वकील को निर्देश दिया था कि वे विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर करें। लेकिन इससे पहले वह ए. वल्लियम्मई को 2 सप्ताह में बिक्री विलेख को निष्पादित करने का एक अंतिम अवसर देना चाहते थे, जब वह शेष बिक्री पर विचार करेंगे। इसके अलावा, 1985 के ओएस नंबर 787 में विभाजन मुकदमे को 04.07.1991 पर डिफॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया था। गलत सर्वेक्षण सीमांकन अर्थात् न्यास से संबंधित भूमि को इस तरह से ठीक किया गया कि न्यास की संपत्ति पूर्व में और सूट संपत्ति पश्चिम में स्थित थी।

8. ए. वल्लियम्मई ने एस-14 को प्रदर्शित करने के लिए दिनांकित 16.09.1991 के प्रत्युत्तर के माध्यम से जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया कि एक बिक्री विलेख को निष्पादित किया जा सकता है और विशेष रूप से लागू किया जा सकता है। यह स्वीकार करते हुए कि 1985 के ओ. एस. सं. 787 में विभाजन मुकदमे को चूक के लिए खारिज कर दिया गया था, यह कहा गया था कि इसकी बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। सूट को बहाल किया जा सकता है। ए. वल्लियम्मई ने दावा किया कि वह अनपढ़ थी। हालाँकि उन्हें राजस्व कार्यालय ले जाया गया था, लेकिन वह अपने द्वारा दिए गए बयान की सामग्री के बारे में अनजान थीं। किसी भी स्थिति में, संपत्ति के आदान-प्रदान के लिए एक पंजीकृत दस्तावेज की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण कार्यवाही में विभाजन विलेख को ठीक नहीं किया जा सकता है।

9. आई. डी. 1 पर, के. श्रीराम फाई ने 1991 की ओ. एस. संख्या 1508 में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे का नेतृत्व किया, जिसमें ए. वल्लियम्मई को तब तक सूट संपत्ति से निपटने से रोका गया जब तक कि वह बिक्री विलेखों को निष्पादित नहीं करती। ए. वल्लियम्मई, यह आरोप लगाया गया था कि सूट संपत्ति को बेचने के लिए तीसरे पक्ष के साथ बातचीत कर रहा था। के. श्रीराम 189 वर्ष के होंगे।

ए. वल्लियम्मई बनाम केपी. मुराली और अन्य [संजीव खन्ना, जे.] 190

कम समय में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, और अपने नोटिस के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था।

10. ए. वल्लियम्मई ने मुकदमे का विरोध किया, और अपने लिखित बयान में, उन्होंने आरोप लगाया था कि के. श्रीराम कभी भी बेचने के लिए समझौते को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे (ए-1 प्रदर्शित करें)। इसलिए उन्होंने विशिष्ट प्रदर्शन के बजाय निषेधाज्ञा के मुकदमे का नेतृत्व किया था। उन्होंने दावा किया था कि समय अनुबंध का सार है। उन्होंने आई. डी. 1 तक समय बढ़ाने के लिए सहमति दी थी, लेकिन के. श्रीराम ने उस तारीख तक शेष बिक्री का भुगतान नहीं किया था। सूट संपत्ति ए. गोपालकृष्णन को पट्टे पर दी गई थी, जो कब्जे में था और भूमि पर खेती कर रहा था।

11. निचली अदालत ने के. श्रीराम के पक्ष में और ए. वल्लियम्मई के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया था। हालाँकि, 23.12.1992 पर मुकदमा खारिज कर दिया गया क्योंकि दबाव नहीं डाला गया था। एक नया सूट पहनने की स्वतंत्रता न तो प्रार्थना की गई थी और न ही दी गई थी।

12. 23.12.1992 पर ही, के. श्रीराम ने प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में बेचने (ए-1 प्रदर्शित करने) के समझौते के तहत अपने अधिकार सौंपे। 1 – के. पी. मुरली और प्रतिवादी नं. 2 – एस. पी. दुरैसामी, दिनांक 23.12.1992 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, ए-2 प्रदर्शित करें।

13. के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी ने 1994 के ओ. एस. सं. 1651 में ए. वल्लियम्मई को सूट संपत्ति से निपटने से रोकने के अनुरोध के साथ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया। बिक्री के लिए समझौते (प्रदर्शनी ए-1) के विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए आदेश की प्रार्थना नहीं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी।

14. 02.05.1995 पर, ए. वल्लियम्मई ने 5 एकड़, सूट संपत्ति का एक हिस्सा, बी. नमीचंद जैन और तीन अन्य लोगों को रु. 7,50,000 की बिक्री के लिए बेच दिया। खरीदारों को सूट संपत्ति के ऐसे हिस्सों के कब्जे में रखा गया और उनका आनंद लिया गया।

15. 1994 के ओ. एस. सं. 1651 में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी ने 1995 के ओ. एस. सं. 1126 में विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे का नेतृत्व किया, जिसे बाद में 2004 के ओ. एस. सं. 21 के रूप में पुनर्नामित किया गया। वर्तमान अपील उक्त मुकदमे में निचली अदालत के फैसले और डिक्री से उत्पन्न होती है, जिसे बाद में उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में जोड़ा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

16. ए. वल्लियम्मई द्वारा मुकदमे का बचाव कई आधारों पर किया गया था, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, रचनात्मक न्याय व्यवस्था, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध, सीमा की 6 बार, बेचने के लिए समझौते को पूरा करने की तैयारी और इच्छा दिखाने में विफलता (ए-1 प्रदर्शित करें) और असाइनमेंट समझौते की अयोग्यता (ए-2 प्रदर्शित करें) शामिल हैं।

17. निचली अदालत ने एक मुद्दा तैयार किया, वह यह है कि क्या वादी विशिष्ट ग निष्पादन की राहत के हकदार थे। ट्रायल कोर्ट ने माना कि बेचने के समझौते (प्रदर्शनी ए-1) के निष्पादन और अनुमोदन (प्रदर्शनी ए-3) के माध्यम से छह महीने तक इसके विस्तार को स्वीकार किया गया था। ए. वल्लियम्मई ने ट्रस्ट को पूर्व की ओर भूमि के आवंटन या अग्रिम राशि वापस करने की उनकी इच्छा के बारे में कोई सबूत नहीं दिया था। इसके अलावा, के. श्रीराम को 1985 के ओ. एस. संख्या 787 में विभाजन मुकदमे की स्थिति के बारे में पता नहीं था। संहिता के आदेश VIII, नियम 4 और 5 के संदर्भ में, ए. वल्लियम्मई ने बेचने के समझौते (प्रदर्शनी ए-1) को पूरा करने के अपने इरादे से इनकार नहीं किया था। के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी ने 1985 के ओ. एस. संख्या 787 में विभाजन मुकदमे के समापन की प्रतीक्षा की थी। इसलिए 30.04.1993 पर उक्त विभाजन मुकदमे के निपटारे तक सीमा अवधि शुरू नहीं हुई थी। तदनुसार, रेस जुडिकाटा की याचिका को खारिज कर दिया गया था क्योंकि विशिष्ट सी प्रदर्शन के मुकदमे को सही नहीं ठहराने के निर्णय को वास्तविक माना जाता था। के. श्रीराम बेचने के समझौते (ए-1 को प्रदर्शित करने) को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थे क्योंकि उन्होंने सूट संपत्ति को आवास भूखंडों में विभाजित करने के लिए कदम उठाए थे। यह तर्क कि समनुदेशन समझौता (प्रदर्शनी ए-2) के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, खारिज कर दिया गया।

18. उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में 1985 के ओ. एस. संख्या 787 में विभाजन वाद के लंबित होने को देखते हुए संहिता के आदेश II, नियम 2 के तहत न्यायिक या बार की याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालाँकि, ट्रस्ट की संपत्ति का पूर्व की ओर आवंटन को बेचने के समझौते (ए-1 प्रदर्शित करें) के लिए गैर-आवश्यक माना गया था। उच्च न्यायालय निचली अदालत से सहमत था कि के. श्रीराम सूट संपत्ति खरीदने के लिए तैयार और इच्छुक थे और उन्होंने बिक्री विलेखों को निष्पादित करने के लिए कदम उठाए थे। के. श्रीराम ने 1991 के ओ. एस. सं. 1508 में निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे के दौरान विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखा था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था क्योंकि उस पर दबाव नहीं डाला गया था।

6 संक्षेप में, "कोड"।

19. हमें शुरुआत में ही यह दर्ज करना चाहिए कि अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विवाद में काफी बल है जो रचनात्मक न्यायपालिका या संहिता के आदेश II, नियम 2 के सिद्धांत पर निर्भर है। लेकिन हम इन दलीलों पर कोई सकारात्मक राय नहीं दे रहे हैं। अपीलार्थियों को इस अपील में सफल होना चाहिए क्योंकि 2004 की ओ. एस. संख्या 21 में विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए मुकदमा स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के सीमा द्वारा वर्जित है। प्रासंगिकता से बचने के लिए, पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए तर्कों को हमारी चर्चा और तर्क में संदर्भित किया जाएगा।

20. सीमा अधिनियम, 1963 7 की अनुसूची के भाग II के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट ग निष्पादन के लिए मुकदमे को दायर करने के लिए सीमा अवधि निर्धारित की गई है जो निष्पादन के लिए दायर की गई तारीख से तीन साल है, और वैकल्पिक रूप से जब कोई तारीख निर्धारित नहीं की जाती है, उस तारीख से तीन साल जब वादी को पता चलता है कि निष्पादन से इनकार कर दिया गया है। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 9 में कहा गया है कि एक बार सीमा अवधि शुरू हो जाने के बाद, यह किसी भी बाद की अक्षमता या मुकदमा दायर करने या आवेदन करने में असमर्थता के बावजूद चलता रहता है।⁹

21. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि रु। 1,00,000-का भुगतान बेचने के समझौते के निष्पादन के समय किया गया था (ए-1 प्रदर्शित करें), और रु। 31,45,000 का भुगतान 26.05.1989 द्वारा किया जाना आवश्यक था। Rs.31,45,000/- के भुगतान और बिक्री विलेख के निष्पादन का समय समर्थन (प्रदर्शनी ए-3) के माध्यम से 26.11.1989 तक बढ़ाया गया था। अगर हम तारीख लेते हैं

7 संक्षेप में, "अनुच्छेद 54"।⁸ अनुसूची

XXX

सूट का विवरण	सीमा की अवधि	जिस समय से अवधि शुरू होती है
5 4. एफ. ओ. आर. एस. पी. ई. सी. आई. सी. पी. ए. एन. सी. ई. ओ. एफ. एक अनुबंध।	तीन साल	प्रदर्शन के लिए निर्धारित तिथि, या, यदि ऐसी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, जब वादी को नोटिस है कि प्रदर्शन से इनकार कर दिया गया है।

9 समय का निरंतर चलना: जहाँ एक बार समय चलना शुरू हो गया है, वहाँ बाद में कोई अक्षमता या मुकदमा दायर करने या आवेदन करने में असमर्थता इसे नहीं रोकती है। बशर्ते कि जहां किसी लेनदार की संपत्ति को प्रशासन के पत्र उसके देनदार को दिए गए हैं, वहां ऋण की वसूली के लिए मुकदमे के लिए सीमा की अवधि का संचालन तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि प्रशासन जारी रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

26.11.1989 प्रदर्शन की तारीख के रूप में, 27.09.1995 पर निर्दिष्ट सी प्रदर्शन फाई के लिए मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है। हालाँकि, हम के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी की ओर से उठाए गए निवेदन से सहमत हैं, कि उपरोक्त समय, जैसा कि बेचने के समझौते और समर्थन (ए-1 और ए-3 को प्रदर्शित करें) द्वारा निर्धारित किया गया था, अनुबंध का सार नहीं था और

इसलिए, अनुच्छेद 54 का पहला भाग लागू नहीं होगा।¹⁰ इसके बजाय, अनुच्छेद 54 का दूसरा भाग लागू होगा।¹¹ अनुच्छेद 54 की व्याख्या पर, इस न्यायालय ने

पचानन धारा और अन्य बनाम मोनमाता नाथ मैती 12 ने माना है कि

प्रथम या द्वितीय भाग की प्रयोज्यता का निर्धारण करते हुए, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या बेचने के समझौते के निष्पादन के लिए किसी समय निर्धारित किया गया था और यदि ऐसा किया गया था, तो क्या मुकदमा निर्धारित अवधि से परे दायर किया गया था, जब तक कि समय या प्रदर्शन के विस्तार के लिए कोई मामला अनुरोध या स्थापित नहीं किया गया था। हालांकि, जब प्रदर्शन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता है, तो अदालत को उस तारीख को निर्धारित करना होगा जिस पर वादी को प्रतिवादी की ओर से अनुबंध करने से इनकार करने की सूचना मिली थी। इसलिए, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या के. श्रीराम या उनके नियुक्त व्यक्तियों, के. पी. मुरली या एस. पी. दुरैसामी ने ध्यान दिया था कि ए. वल्लियम्मई द्वारा प्रदर्शन को अस्वीकार कर दिया गया था और यदि ऐसा है, तो किस तारीख से।²² हमने पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है, अर्थात्, दिनांकित 11.07.1991 (ए-6 प्रदर्शित करें), दिनांकित 09.08.1991 (ए-7 प्रदर्शित करें), दिनांकित 31.08.1991 (एस-13 प्रदर्शित करें) और दिनांकित 16.09.1991 (एस-14 प्रदर्शित करें) का जवाब। हमने ए. वल्लियम्मई के नेतृत्व में लिखित बयान का भी उल्लेख किया है। ये स्वीकृत दस्तावेजी साक्ष्य हैं और इसकी सामग्री बहस में नहीं है। हमारी राय में, के. श्रीराम ने दिनांकित 11.07.1991 (प्रदर्शनी ए-6) और प्रत्युत्तर सूचना दिनांकित 31.08.1991 (प्रदर्शनी एस-13) में स्वीकार किया था कि ए. वल्लियम्मई ने अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया था। के. श्रीराम फाई ने ए. वल्लियम्मई को सूट संपत्ति को तीसरे पक्ष को बेचने से रोकने के लिए 15.07.1991 पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे का नेतृत्व किया। शिकायत में, एक विशिष्ट कथन और कथन है कि ए. वल्लियम्मई बहाना बना रहे थे और पहले से सहमत शर्तों से पीछे हट रहे थे। ए. वल्लियम्मई सूट संपत्ति की बिक्री के लिए तीसरे पक्ष के साथ बातचीत कर रहे थे। वह तिरुवेरम्बुर पंचायत संघ के समक्ष दिए गए बयान का पालन नहीं कर रही थीं। के.

10 सुप्रा नोट 8. 11 ऊपर टिप्पणी 8.

12 (2006) 5 एससीसी 340।

193

ए. वल्लियम्मई बनाम के.पी. मुरली और अन्य [संजीव खन्ना, जे.] 194

श्रीराम ने कहा था कि वह थोड़े ही समय में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट तैयार करने जा रहे हैं और वह ए. वल्लियम्मई के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ए. वल्लियम्मई द्वारा दिनांकित 09.08.1991 (प्रदर्शनी ए-7) और उत्तर दिनांकित 16.09.1991 (प्रदर्शनी एस-14) ने स्थिति को नहीं बदला। ये अस्वीकृति की लिखित सूचनाएँ हैं न कि किसी दायित्व और संबंध की स्वीकृति की। के. श्रीराम ने इस आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा वापस नहीं लिया कि वह ए. वल्लियम्मई के जवाब और रुख से संतुष्ट थे और इसलिए कार्रवाई का कारण नहीं बचा। के. श्रीराम ने मुकदमा जारी रखा और उनके पक्ष में दिए गए अस्थायी निषेधाज्ञा का लाभ उठाया। जिस दिन के. श्रीराम ने के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी (प्रदर्शनी ए-2) के पक्ष में बेचने (प्रदर्शनी ए-1) के समझौते के तहत अपने अधिकारों को हस्तांतरित/सौंपा था, उस दिन मुकदमे को बिना शर्त खारिज कर दिया गया था। के. श्रीराम, के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी को इनकार के बारे में पता था और इस प्रकार कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो गया था जिससे उन्हें ए. वल्लियम्मई के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

23. हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि निचली अदालत के सामने पीडब्लू-2 के रूप में ए. वल्लियम्मई के बयान में, उन्होंने स्वीकार किया था कि के. श्रीराम को बेचने के समझौते (प्रदर्शनी ए-1) के तहत निर्धारित तिथि पर शेष बिक्री विचार का भुगतान करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था और वह इस उम्मीद के साथ चुप रही कि के. श्रीराम दिखाएंगे और इसलिए अनुच्छेद 54 के दूसरे भाग के तहत सीमा अवधि शुरू नहीं हुई थी। हम सहमत नहीं हैं। जिस प्रश्न की जांच और उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि क्या के. श्रीराम को ए. वल्लियम्मई के इनकार करने या समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने की अनिच्छा का

पता था।पीडब्लू-2 के रूप में ए. वल्लियम्मई के बयान का प्रासंगिक हिस्सा उनके इनकार या स्वीकृति का उल्लेख नहीं करता है, बल्कि केवल इस तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख करता है कि उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया था या एक समय पर उन्हें उम्मीद थी। इस बयान को ए. वल्लियम्मई की स्वीकृति और इच्छा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। दोहराव के जोखिम पर, हम कहते हैं कि दिनांकित 09.08.1991 (प्रदर्शनी ए-7) और उत्तर दिनांकित 16.09.1991 (प्रदर्शनी एस-14) में, ए. वल्लियम्मई ने के. श्रीराम द्वारा उनके खिलाफ किए गए दावों या आरोपों का विरोध किया था, और उनके इनकार और बिक्री के समझौते (प्रदर्शनी ए-1) का पालन करने और उसका पालन करने से इनकार किया गया था।

24. एक बार जब हम ए. वल्लियम्मई के इनकार और के. श्रीराम के इनकार के नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं, तो के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी की ओर से भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 63 पर भरोसा करते हुए कहा जाता है कि एक वादा किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

एस के आधार पर अनुबंध के प्रदर्शन और प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाएँ।

ब्रह्मानंद और ओआरएस. वी.के. आर. मुतुगोपाल 13, समय के विस्तार की आवश्यकता

लिखित रूप में नहीं होना चाहिए और मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, जिसमें दूसरे पक्ष की ओर से आचरण और सहनशीलता शामिल है, को अस्वीकार करना होगा। इनकार और सहनशीलता विपरीत हैं।

25. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में इस तर्क को खारिज कर दिया था कि पूर्व की ओर न्यास की संपत्ति के आवंटन का विशिष्ट कार्य निष्पादन के लिए मुकदमे की भाषा पर कोई असर पड़ता है। हम उक्त कथन से सहमत हैं। वास्तव में, आई. डी. 1 (प्रदर्शनी एस-13) के प्रत्युत्तर के माध्यम से, के. श्रीराम ने कहा कि सर्वेक्षण मानचित्र में सर्वेक्षण सीमांकन को पहले से ही इस तरह से सही किया गया था कि ट्रस्ट की संपत्ति पूर्व में और ए. वल्लियम्मई की संपत्ति पश्चिम में स्थित थी।

26. यह कहना कि बेचने का समझौता (ए-1 प्रदर्शित करें) 1985 के ओ. एस. संख्या 787 में विभाजन मुकदमे के निपटारे के बाद ही विशिष्ट रूप से किया जाना था, गलत और गलत है। हमने बेचने के समझौते (प्रदर्शनी ए-1) के प्रासंगिक खंड को उद्धृत किया है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि बिक्री विलेख को विभाजन मुकदमे के निपटारे के बाद ही निष्पादित किया जाना था। ए. वल्लियम्मई ने केवल ईमानदारी से कहा था कि विभाजन के मुकदमे के अलावा सूट संपत्ति पर कोई बोझ या विवाद नहीं था। विवादित सूट संपत्ति को अभी भी बेचा और स्थानांतरित किया जा सकता था। के. श्रीराम को बिक्री के समझौते (प्रदर्शनी ए-1) को निष्पादित करते समय लंबित मुकदमे के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, जो लंबित मुकदमेबाजी के बावजूद सहमत था। के. पी. मुरली और दुरैसामी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि ए. वल्लियम्मई ने अपने दिनांकित 09.08.1991 (प्रदर्शनी ए-7) के जवाब में दावा किया कि उनके लिए उक्त विभाजन मुकदमे के निपटारे तक अनुबंध को निष्पादित करना संभव नहीं था। यह तर्क बिना किसी योग्यता के है, क्योंकि ए. वल्लियम्मई का यह दावा दर्शाता है कि उन्होंने बेचने के समझौते को पूरा करने से इनकार कर दिया था (ए-1 प्रदर्शित करें)। उक्त मुकदमे में एक निर्णय बिक्री के समझौते (ए-1 प्रदर्शित करें) के तहत बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं थी। न तो के. श्रीराम ने उक्त विभाजन मुकदमे में निर्णय के बाद बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए ए. वल्लियम्मई द्वारा सहमति या स्वीकृति के रूप में उक्त उत्तर को पढ़ा था। दूसरी ओर, जैसा कि पहले दर्ज किया गया था, के. श्रीराम ने 1991 के ओ. एस. संख्या 1508 में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे पर दबाव डालना जारी रखा था। के. पी. मुरली और के. पी. दुरैसामी की ओर से उठाए गए तर्क में एक और भ्रान्ति है

कि ए. वल्लियम्मई का दिनांकित 09.08.1991 (प्रदर्शनी ए-7) का जवाब पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा रहा है। यह किसी सूचना या जवाब और उसकी सामग्री और उद्देश्य को समझने का उचित तरीका नहीं है। के. श्रीराम, और बाद में, के. पी. मुरली और के. पी. दुरैसामी ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था।

27. उपरोक्त कारणों से, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए 3 साल की सीमा अवधि तब शुरू हुई जब के. श्रीराम ने 15.07.1991 पर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था। ए. वल्लियम्मई का दिनांक 09.08.1991 (ए-7 प्रदर्शित करें) का जवाब या दिनांक 16.09.1991 (एस-14 प्रदर्शित करें) का जवाब फिर से के. श्रीराम को उनके इनकार और बेचने के समझौते को पूरा करने की अनिच्छा (ए-1 प्रदर्शित करें) के लिए पर्याप्त लिखित नोटिस था। अनुच्छेद 54 के दूसरे भाग के तहत तीन साल की सीमा अवधि, जो उस तारीख से है जब पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा इनकार करने की सूचना मिली थी, तब समाप्त हो गई थी जब विशिष्ट सी प्रदर्शन के लिए मुकदमा 27.09.1995 पर दायर किया गया था। 2004 के ओ. एस. सं. 21 में मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है।

28. तदनुसार, विशेष ग निष्पादन के लिए विवादित निर्णय और डिक्री, जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा लागू किया गया है, को दरकिनार कर दिया जाता है।

29. के. श्रीराम ने रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। 1,00,000-से ए. वल्लियम्मई। यह पद स्वीकार किया जाता है। हमारे निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी के नेतृत्व में दायर मुकदमे में, सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण, के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी ब्याज के साथ रुपये की वापसी के लिए डिक्री के हकदार नहीं हैं। सुनवाई के दौरान, पक्षों ने एक समझौते पर बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन यह वास्तविक नहीं था। ए. वल्लियम्मई रुपये देने के लिए सहमत हो गए थे। 50,00,000- (केवल पचास लाख रुपये) के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी को। इसका कारण यह था कि के. श्रीराम ने लेआउट योजनाओं की मंजूरी प्राप्त करने में पैसा खर्च किया था। ए. वल्लियम्मई ने लगभग 1 एकड़ भूमि को छोड़कर अधिकांश सूट संपत्ति बेच दी है। के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी ने रु. 31,45,000- उनके पक्ष में पारित डिक्री के संदर्भ में, जो राशि जमा रसीद (ओं) के आधार पर ब्याज में परिवर्तित कर दी गई है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, ए. वल्लियम्मई को के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी को Rs.50,00,000/- (केवल पचास लाख रुपये) का भुगतान करने के निर्देश के साथ पर्याप्त न्याय करने के लिए। इस शुल्क में 26.05.1988 पर भुगतान किए गए रु. 1,00,000 के अग्रिम और के. श्रीराम द्वारा किए गए खर्च और ब्याज आदि को ध्यान में रखा जाता है। उपरोक्त शर्तों में ए. वल्लियम्मई के खिलाफ के. पी. मुरई और एस. पी. दुरैसामी के पक्ष में <आईडी1,00,000/- का फरमान पारित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि ए. वल्लियम्मई द्वारा 6 (छह) महीनों के भीतर <आईडी1,00,000/- का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। 50,00,000- इस निर्णय की तारीख से उस तारीख तक जिस पर वास्तव में भुगतान किया जाता है।

30. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, एस. जयप्रकाश और अन्य, ए. जयकुमार और अन्य, और एस. बालासुब्रमण्यम और अन्य द्वारा 2023 की सिविल अपील संख्या 5343, 5344 और 5345 को अनुमति दी जाती है और के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी के पक्ष में निर्दिष्ट सी प्रदर्शन का आदेश पारित किया जाता है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1, तिरुचिरापल्ली द्वारा निर्णय लिए जाने पर के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी द्वारा 2004 के ओ. एस. नंबर 21 को खारिज माना जाएगा। ए. वल्लियम्मई द्वारा 2023 की सिविल अपील संख्या 5342 को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि वाद भूमि के संबंध में विशिष्ट ग निष्पादन की डिक्री को अलग रखा जाता है, और इसके स्थान पर 5 लाख रुपये के डिक्री द्वारा

प्रतिस्थापित किया जाता है। 50,00,000-इस निर्णय की तारीख से प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ ई. एफ. ई. सी. टी. के साथ देय जो ए. वल्लियम्मई रुपये का भुगतान करने में विफल रहने पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। 50,00,000-इस फैसले की तारीख से छह महीने के भीतर। 2004 का ओ. एस. सं. 21, के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी के नेतृत्व में और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं. 1, तिरुचिरापल्ली द्वारा निर्णय लिया गया, ए. वल्लियम्मई के खिलाफ उपरोक्त शर्तों में फैसला सुनाया गया है। 31. के. पी. मुरली और एस. पी. दुरैसामी अपने द्वारा पहले जमा की गई राशि को वापस लेने के हकदार हैं, ट्रायल कोर्ट के डिक््री के संदर्भ में उस पर उपार्जित ब्याज के साथ।

32. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे